प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

17.11.2025/प्रादेशिक समाचार/1945 बजे

"आज के मुख्य समाचार"

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल का 7 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जारी करने का केंद्र से किया आग्रह।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों की संरचना, वर्गीकरण व सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायतीराज चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार व चुनाव आयोग से 21 दिसंबर तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आया हैल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार व भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप।

अब समाचार विस्तार से.....

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ की भूमि व परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश का 7 दशमलव एक–नौ प्रतिशत हिस्सा जारी करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड से लंबित बकाया राशि जारी करने और बी.बी.एम.बी. में हिमाचल से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी की नीति लागू करने और हिमाचल की मुफ्त रॉयल्टी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का अनुरोध भी किया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 40 वर्ष पूरे कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य को सौंपने सहित निर्माणाधीन किशाऊ व रेणुका बांध जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत घटकों के लिए पूर्ण केंद्रीय वित्त पोषण की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन मानदंडों में उचित संशोधन का आग्रह भी किया। बैठक के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश व लद्दाख के बीच सरचू और शिंकुला क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने का अनुरोध भी किया।

चुनाव आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2020 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू करते हुए प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों की संरचना, वर्गीकरण व सीमाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर सकेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता..... 57''—

डिस्पैच— प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों की संरचना, वर्गीकरण और सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पंचायत या नगर पालिका की सीमाओं, वर्गीकरण या संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आयोग ने ये कदम उन स्थानीय निकायों के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है, जिनका कार्यकाल अगले वर्ष के शुरूआत में समाप्त हो रहा है। आयोग द्वारा प्रदेश की सभी 3 हज़ार 5 सौ 77 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 ज़िला परिषदों और 71 नगर निकायों का परिसीमन पूरा कर अंतिम रूप से अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने 3 हज़ार 5 सौ 48 ग्राम पंचायतों व 70 स्थानीय शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी हैं, जबकि शेष पंचायतों व स्थानीय शहरी निकायों की सूची एक और 7 दिसंबर को प्रकाशित की जाएंगी।

पंचायत चुनाव

इस बीच प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब कर 21 दिसंबर तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। पंचायतीराज चुनावों की समय सीमा को लेकर दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की मंशा समय पर चुनाव करवाने की नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनदीप चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझ कर चुनाव में देरी कर रही है, जिससे पंचायत प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।

जगत नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये बात आज उन्होंने किन्नौर ज़िला के निचार उपमंडल की सुंगरा पंचायत में बनाए गए स्वागत द्वार भावानगर के उद्घाटन अवसर पर कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हित में अनेक निर्णय ले रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समावेशी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलों से युवाओं का मानसिक, शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने में भी मदद मिलती है। सोलन स्थित राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय में एन.एस.यू.आई. द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास के लिए युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशा समाज के लिए एक चुनौती बन गया है। शांडिल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करने का आह्वान किया।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आया हैल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भर्ती प्रकिया में न कोई नियम स्पष्ट है और न ही किसी तरह का कानून। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों से पहले आया हैल्पर भर्ती कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है और पंचायत चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की हर योजना प्रदेशवासियों को गुमराह करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और मित्र मंडली को लाभ पहुंचाने का साधन बन रही है।

सुरेश कश्यप

भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र से पदयात्रा को शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के लिए एक भारत–श्रेष्ठ भारत का विचार सर्वोपरि था। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास की भाग्य रेखाएं हैं और सड़कों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये बात आज उन्होंने शिमला ज़िले के कोटखाई उपमंडल में एक करोड़ 19 लाख रूपये की लागत से बनी धनद्रोंटी–केहमली सड़क के उद्घाटन अवसर पर कही।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा ज़िले के राजकीय महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय रेहन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 बहुतकनीकी महाविद्यालयों की 2 सौ 12 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि खेलना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि इनसे टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

राजेश धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश के पुलिस जवान अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उन्होंने आज सिरमौर ज़िला के धौलाकुआं में छठी भारत आरक्षित वाहिनी के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन पुलिस जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान को याद करने का दिन है। राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में पुलिस कर्मचारियों की डाईट मनी को 2 सौ 10 रूपये से बढ़ाकर एक हज़ार रूपये किया गया।

''अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल का 7 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जारी करने का केंद्र से किया आग्रह।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों की संरचना, वर्गीकरण व सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायतीराज चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार व चुनाव आयोग से 21 दिसंबर तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आया हैल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार व भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप।